(ग) क्या सरकार अपने प्रक्षेपास्त्रों की पास (रेंज) में वृद्धि करने पर विचार करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० वी० एन० सोमू): (क) जी हाँ।

(ख) 16 उड़ान परीक्षण किए जा चुके हैं। सेना के लिए "पृथ्वी" के 150 कि०मी० वाले रूपांतरण का विकास सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है और इसके बाद के कार्यकलाप चल रहे हैं। इसे सेना में शामिल करने से पूर्व इसके और अधिक परीक्षण किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अंतिम उड़ान परीक्षण किए जाने से वायुसेना के लिए "पृथ्वी" के 250 कि०मी० वाले रूपांतरण का भी विकास सफतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।

(ग) वायुसेना के लिए "पृथ्वी" को रेंज पहले ही 250 कि०मी० तक बढ़ा दी गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Handing over of Hakimpet Airport for making International Airport

3373. DR. ALLADI P. RAJKUMAR: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether the Government of Andhra Pradesh has requested the handing over of the Hakimpet Airport for making it an international one; and

(b) if so, the terms and conditions thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI N.V.N. SOMU): (a) and (b) A proposal was received from the State Government of Andhra Pradesh for handing over of the IAF airport at Hakimpet for making it an international airport. However, due to certain technical inadequacies, they have been requested to re-examine the whole issue in consultation with DGCA and Airport Authority of India.

Changes in training content of NCC

3374. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether Government are considering radical changes in training content and structure of NCC Organisation in terms of upgradation expansion change;

(b) if so, the details thereof;

(c) the details of present organisation set-up and coverage, State-wise and proposed expansion; and

(d) the details of major changes and proposed projects to be taken up during current year?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI N.V.N. SOMU): (a) to (d) Under the command and control of Director General NCC, New Delhi, there are 16 Directorates, 91 Group Headquarters and 754 Units in the country. The State-wise details of NCC Units is enclosed as a statement. (*see* below) There is no proposal to make any radical changes in NCC during the current year.

Statement

State-wise details of N.C.C. Units

Sl. No.	State(s)	No. of Units	Total No. of Districts	No. of Districts covered by NCC
1.	Andhra Pradesh	57	23	23
2.	Bihar	43	55	55
3.	Delhi	18	09	09
4.	Gujarat	35	19	19
5.	Jammu & Kashmir	09	14	14
6.	Karnataka	49	20	20

Sl. No.	State(s)	No. of Units	Total No. of Districts	No. of Districts covered by NCC
7.	Goa	03	01	01
8.	Kerala	38	14	14
9.	Madhya Pradesh	51	45	45
10.	Maharashtra	59	31	31
11.	Assam	26	23	23
12.	Arunachal Pradesh	01	11	11
13.	Manipur	03	08	06
14.	Meghalaya	04	07	07
15.	Mizoram	01	03	02
16.	Nagaland	04	07	06
17.	Tripura	03	03	03
18.	Orissa	23	30	30
19.	Punjab	29	17	17
20.	Haryana	17	12	12
21.	Himachal Pradesh	12	12	12
22.	Rajasthan	35	30	30
23.	Tamil Nadu	51	29	29
24.	Uttar Pradesh	122	68	66
25.	West Bengal	50	18	18
26.	Sikkim	—	04	04
Union Territories				
1.	Chandigarh	04	01	01
2.	Diu & Daman	—	02	01
3.	Dadar & Nagar Haveli	—	01	01
4.	Lakshadweep	—	01	01
5.	Pondicherry	05	04	04
6.	Andaman & Nicobar	02	02	02

रक्षा कार्मिकों के लिए बुनकरों से वस्त्रों और अन्य वस्तुओं का खरीदा जाना

3375. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका मंत्रालय देश में बुनकरों, हस्तशिल्पियों और महिला संगठनों से उनके द्वारा निर्मित कम्बल, वस्त्र, जूते और अन्य वस्तुएं खरीद कर उन्हें प्रोत्साहित कर रहा है और सेना के तीनों स्कंधों को उन वस्तुओं की आपूर्ति कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन राज्यों के ऐसे उद्यमियों से तीनों सेनाओं के लिए कुल कितने मूल्य की वस्तुएं खरीदी गई हैं;

(ग) क्या मंत्रालय ऐसे बुनकरों को कुछ रियायतें और प्रोत्साहन देने का विचार रखता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० वी० एन० सोमू): (क) से (घ) रक्षा मंत्रालय बैरक कंबल, अस्पताल के लिए भूरे रंग के कंबल, हस्त तौलियों, आई टी दरियों आदि के वास्ते मैसर्स एसोशिएसन आफ कापोरैशन एंड एपेक्स सोसाइटीज आफ हैंडलूम (ए सी ए एस एच), नई दिल्ली, मैसर्स महिला विकास संगठन (डब्ल्यु डी ओ) नई दिल्ली, मैसर्स खादी ग्रामोद्योग आयोग (के वी आई सी), मुंबई और हरियाणा के जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण को इस संबंध में सरकारी अनुदेशों के अनुरूप आदेश दे रहा है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान इन संगठनों को तीनों सेना मुख्यालयों द्वारा दिए गए आदेशों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है **(नीचे देखिए)**

इन क्षेत्रों को अधिक रियायतें और प्रोत्साहन दिए जाने का मुद्दा कपड़ा मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय तथा पूर्ति विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है जो इस विषय के संबंध में नोडल मंत्रालय हैं।